भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 2098

15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

ऋणेतर सहकारी समितियां

2098. डॉ. विष्णु प्रसाद एम.के.:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में चल रही ऋणेतर सहकारी समितियों के आंकड़े रखने हेतु कोई प्रभावी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में ऋणेतर सहकारी समितियों को वर्गीकृत करने और इनके बेहतर प्रदर्शन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसी समितियों को मामले के आधार पर वित्तीय सहायता देने की कोई संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): वर्तमान में, सहकारिता मंत्रालय के पास सहकारी समितियों का कोई आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। सहकारिता मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऋणेतर सहकारी समितियों पर जानकारी प्राप्त करेगा। इस संबंध में, मंत्रालय ने डेटाबेस में शामिल करने के लिए विभिन्न मापदंडों, प्रक्रियाओं और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।

(घ): वर्तमान में, सहकारिता मंत्रालय देश भर में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए केवल कृषि सहकारिता पर केंद्रीय क्षेत्र समेकित योजना (सीएसआईएसी) कार्यान्वित करता है।

*****